







सामान्य अध्ययन/GENERAL STUDIES: Test – 2349 (2024)

निर्धारित समय: तीन घंटे

Time Allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250

Maximum Marks: 250

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

कुल बीस प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are TWENTY questions printed in HINDI & ENGLISH.

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.







- Q1. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई के बीच मौजूद अंतर की विवेचना कीजिए।

 Discuss the differences between affirmative action in India and the United States. (Answer in 150 words)
- Q2. राज्यों में लोकायुक्तों को उनकी निर्धारित भूमिकाओं को पूरा करने हेतु सक्षम बनाने के लिए अधिक अधिकार देने की मांग की गई है। टिप्पणी कीजिए।
 - There has been a demand to give more teeth to the Lokayuktas in states to enable them to fulfill their envisaged roles. Comment. (Answer in 150 words)
- Q3. भारत में ट्रेड यूनियनों के विकास पर चर्चा कीजिए। वर्तमान समय में उनकी भूमिका किस प्रकार बदल रही है?
 - Discuss the evolution of trade unions in India. How is their role changing in the present times? (Answer in 150 words)
- **Q4.** "भारत में न्याय वितरण को बेहतर बनाने के लिए न्यायपालिका के निचले स्तर पर न्याय प्रशासन में सुधार करना महत्वपूर्ण है।" विवेचना कीजिए।
 - "Improving the administration of justice at the lower level of the judiciary is crucial for enhancing justice delivery in India." Discuss. (Answer in 150 words)
- Q5. भारत में भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की भूमिका की विवेचना कीजिए।
 - Discuss the role of the Commissioner for Linguistic Minorities in safeguarding the constitutional rights of linguistic minorities in India. (Answer in 150 words)
- Q6. आपके विचार में भारत के संघवाद में विषमता किस हद तक अनिवार्य है?
 - To what extent, do you think, asymmetry in India's federalism is a necessity? (Answer in 150 words)
- Q7. यद्यपि अधिकरणों का गठन न्यायपालिका के बोझ को कम करने के लिए किया गया है तथापि भारत में उनके समक्ष अलग तरह की चुनौतियां विद्यमान हैं। विवेचना कीजिए।
 - Although created to de-burden the judiciary, tribunals in India have evolved with their own set of challenges. Discuss. (Answer in 150 words)
- **Q8.** भारत में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए गठित एक संगठन के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की प्रभावशीलता का आकलन कीजिए।
 - Assess the effectiveness of the Central Vigilance Commission (CVC) as an organization mandated for tackling corruption in India. (Answer in 150 words)
- **Q9.** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों (CBI) की प्रस्थिति, शक्तियों और कार्यों को संवर्धित एवं पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। संसदीय पैनल की हालिया अनुशंसाओं के आलोक में चर्चा कीजिए।
 - The institution of CBI needs revitalisation and redefining of its status, powers and functions. Discuss in the light of the recent parliamentary panel recommendations. (Answer in 150 words)
- Q10. "प्रभावी काम-काज का अभाव संसद को विचारशील विधि निर्माण करने और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने की उसकी भूमिका को पूरा करने से रोकता है।" विवेचना कीजिए।
 - "Lack of effective functioning prevents the Parliament from fulfilling its role of deliberative lawmaking and holding the executive accountable." Discuss. (Answer in 150 words)







Q11. "गरीबी, अभाव का एक यथेष्ट संकेतक है जिसका समाधान राज्य आरक्षण के माध्यम से कर सकता है, तािक समानता एवं सशक्तीकरण के संवैधानिक लोकाचार को प्रभावी बनाया जा सके।" इसके आलोक में, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या 103वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत में कल्याण को पुनः परिभाषित कर सकता है।

"Poverty is an adequate marker of deprivation that the state can address through reservations to give effect to the constitutional ethos of equality and empowerment." In light of this, critically examine whether the 103rd Constitutional Amendment Act can redefine welfare in India. (Answer in 250 words)

Q12. आपकी राय में, किस हद तक भारत के संघीय अंतर-सरकारी संस्थान गवर्नेंस संबंधी शेष मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों हेतु संचार एवं संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं?

To what extent, in your opinion, do India's federal inter-governmental institutions provide a crucial platform of communication and dialogue for the Center and states to address the outstanding issues of governance? (Answer in 250 words)

Q13. "1996 के पेसा अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय शासन के प्राथमिक साधन के रूप में स्थापित किया गया था।" अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। उनकी कार्यप्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

"The PESA Act of 1996 established the Gram Sabha as the primary vehicle of local governance in Scheduled Areas." Discuss the challenges faced by Gram Sabhas in Scheduled Areas. What steps need to be taken to improve their functioning? (Answer in 250 words)

Q14. "उच्चतम न्यायालय ने इंटरनेट तक पहुंच को मूल अधिकार घोषित किया है लेकिन सरकार अभी भी लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट पर लगातार प्रतिबंध लगा रही है।" टिप्पणी कीजिए।

"The Supreme Court has declared access to Internet as a fundamental right but the government still imposes frequent Internet bans to maintain public order." Comment. (Answer in 250 words)

Q15. "दल-बदल विरोधी कानून की मौजूदगी ने विधायकों की अपनी पसंद से और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को प्रतिबंधित कर लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है तथा विधानमंडलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को राजनीतिक दलों पर नियंत्रण रखने वाले कुछ लोगों तक ही सीमित कर दिया है।" आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

"The presence of the anti-defection law has undermined democracy by inhibiting legislators from exercising their choice and ability to function independently, and restricted decision making in legislatures to a few who control political parties." Critically examine. (Answer in 250 words)

Q16. भारत में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या यू.एस.ए. में की गई व्याख्या से किस प्रकार भिन्न है? वाद-विधियों की सहायता से विवेचना कीजिए।

In what ways does the interpretation of the right to freedom of speech and expression in India differ from that in the USA? Discuss with the help of case laws. (Answer in 250 words)







- Q17. भारत में स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने में राज्य वित्त आयोगों (SFCs) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की विवेचना कीजिए। इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है?
 - Discuss the role played by the State Finance Commissions (SFCs) in empowering the local governments in India. What reforms are needed to make them more effective? (Answer in 250 words)
- Q18. लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस आलोक में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की विवेचना कीजिए। ऐसे किन सुधारों की आवश्यकता है जिनसे CAG को ज़िम्मेदारियां निभाने में और अधिक प्रभावी बनाया जा सके?

A democracy requires a system of checks and balances to prevent the arbitrary use of power by the elected government of the day. In this light, discuss the role played by the Comptroller and Auditor General of India. What reforms are needed to make the CAG more effective in carrying out its responsibilities? (Answer in 250 words)

- Q19. आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के उपाय भारत में स्थानीय शासन में सुधार लाने में प्रभावी रहे हैं।
 - Critically examine whether the measures to enhance the functioning of the Urban Local Bodies (ULBs) have been effective in improving local governance in India. (Answer in 250 words)
- Q20. आपके अनुसार 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं भारत में जमीनी स्तर पर जवाबदेही में वृद्धि करने और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने में किस हद तक योगदान दे सकती हैं?
 - To what extent, in your opinion, can the recommendations of the 15th Finance Commission contribute to fostering accountability and promoting effective governance at the grassroots level in India? (Answer in 250 words)

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.